International Journal of Research in Finance and Management

P-ISSN: 2617-5754
E-ISSN: 2617-5762
IJRFM 2021; 4(2): 159-160
Received: 08-11-2021
Accepted: 16-12-2021

Anand Krishna Pal
Research Scholar, Niilm University, Kaithal, Haryana, India

Correspondence
Anand Krishna Pal
Research Scholar, Niilm University, Kaithal, Haryana, India

भारत में ई गवर्नेंस की वास्तविक स्थिति एवं संभावनाएं

Anand Krishna Pal

सारांश
भारत में ई गवर्नेंस की वास्तविक स्थिति एवं संभावनाएं अध्ययन भारत में ई शासन की अपार संभावनाओ को दिशा देने का एक प्रयास मात्र है। भारत में ई शासन की वास्तविक स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि सरकारी सूचनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का अहम योगदान रहा है। ई-गवर्नेंस शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व स्थापित करता है अत इस विषय पर अध्ययन करना अत्यन्त ही कारगर होगा।

कूटशब्द : ई शासन, G2G, G2C, G2B, G2E, C2C, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, National Policy on Information Technology

प्रस्तावना:
ई-गवर्नेंस से तात्पर्य किसी भी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं को प्रदान करने हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग। ई-गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य जनहित में सरकार की प्रत्येक जानकारी को सभी नागरिकों हेतु उपलब्ध कराना है। इसके द्वारा सरकार एवं जनता के मध्य सहयोगात्मक ढाँचे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है तथा लोगों से मदद और सलाह लेना, सरकार को लोगों की समस्याओं से अवगत कराना आदि इसमें सम्मिलित होता है। ई-गवर्नेंस शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं प्रोत्साहित करता है साथ ही देश की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुधार हेतु तत्पर है, जिनका उद्देश्य सरकारों, नागरिकों तथा उनके व्यवसायों को आधुनिक विश्व के साथ जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था का मजबूतीकरण करना है। ई-गवर्नेंस शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व स्थापित करता जिससे सूचना और सेवाओं पर सरकारी खर्च को कम किया जा सके।

अध्ययन उद्देश्य
अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत में ई शासन की व्यवस्था को समझना एवं ई शासन की संभावनाओ के विषय में समझ को विकसित करना है।

अध्ययन प्रविधि
इस अध्ययन के अंतर्गत प्रमुख रूप से विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया था जो की मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

भारत में E-Governance की पृष्ठभूमि
1970- भारत में ई शासन की दिशा में प्रथम प्रयास वर्ष 1970 के दौरान स्थापित किया गया विद्युत विभाग जिसमे सूचना और संचार पर लक्ष्य को केंद्रित किया गया था।
1977- इसके पश्चात वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सभी जिला कार्यालयों को पूर्णतया कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम का आरंभ किया गया।
1998- वर्ष 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया गया एवं इसे अगले ही वर्ष केंद्र सरकार द्वारा इसे दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक नवीन मंत्रालय का सृजन किया गया जिसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नाम से जाना जाता है।
2000- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉमन एक्शन कार्य योजना के आगमन के लिए राज्यों के आईटी मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था।
सरकार ने GSIN - National Institute for Smart Government स्मार्ट सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। राज्य सरकारों ने ई-सेवा परियोजना आंध्र प्रदेश भूमि (कर्नाटक), इत्यादि जैसी ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ शुरू कीं।

2006 - इस वर्ष काल में NeGP यानि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना शुरू की गई थी । इसमें 31 MMP यानि मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 समर्थन घटक शामिल हैं । 2012 - इस वर्ष काल में NPIT – National Policy on Information Technology को अपनाया गया ।

E-Governance के प्रकार

1. G2G – Government to Government (सरकार से सरकार तक)
2. G2C – Government to Citizens (सरकार से नागरिकों तक)
3. G2B – Government to Business (सरकार से व्यापार तक)
4. G2E – Government to Employees (सरकार से कर्मचारियों तक)
5. C2C – Citizens to Citizens (नागरिक से नागरिक तक)

1. G2G (Government To Government सरकार से सरकार तक)

इस प्रकार का ई शासन दो या दो से अधिक सरकारों अथवा सरकारी कार्यालयों के मध्य सरकारी सूचनाओं या सेवाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क सूत्र का निर्माण किया जाता है । इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय अन्य किसी मंत्रालयों को वित्तीय संबंधी सूचना देना, या फ़िर खाद्य संबंधी की कोई भी जानकारी कृषि मंत्रालय को देना जैसे कार्य आते हैं ।

2. G2C (Government to Citizens) सरकार से नागरिक तक

ई शासन का यह प्रकार सरकार की नीतियों, सेवाओं, योजनाओं अथवा सूचनाओं को प्रत्येक नागरिकों तक प्रेषित करने के उद्देश्य से साधा जाने वाला संपर्क सूत्र है। इसके अंतर्गत आम आदमी किसी भी विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुँच सकता है । इस प्रकार में आयकर, पानी बिल, रेल का टिकट जैसे कार्य को वहा जाये बिना कर सकते है ।

3. G2B (Government to Business सरकार से व्यापार तक)

ई शासन के इस प्रकार के अंतर्गत सरकारी सूचनाओं, सेवाओं, योजनाओं को व्यवसायों के विकास हेतु एवं उनकी बेहतरी हेतु प्रेषित किये जाने के उद्देश्य से संपर्क का निर्माण किया जाता है । G to B के माध्यम से व्यापारी घर बैठे अपने सरकारी कार्यों को आसानीपूर्वक पूर्ण कर सकते है ।

4. G2E (Government to Employees) सरकार से कर्मचारियों तक)

इस प्रकार के ई शासन का प्रयोग सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ सूचनाओं के संप्रेषण में किया जाता है । इसमे सरकार अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करती है, उसी को G2E यानि गवर्मेंट टू एम्प्लोयेस-सरकार से कर्मचारी कहते है ।

5. C2C – नागरिक से नागरिक तक

E-Governance के C to C यानि नागरिक से नागरिक इस प्रकार में नागरिकों का आपसी संपर्क आता है, इसी प्रकार को ही सिटिज़न टू सिटिज़न कहते है ।

ई शासन की संभावनाएं

वर्तमान परिदृश्य में भारत में अनेको ऐसे ग्रामीण क्षेत्र उपस्थित हैं जहाँ तक इंटरनेट की सुविधाओं का सर्वदा अभाव है । अत ई शासन के लाभ को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों को इंटरनेट जैसे सुविधाओं से परिपूर्ण करने की संभावनाएं विकसित हुई हैं । वर्तमान भारत में आज भी बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित एवं पिछड़ी है अत बिना शिक्षा के ई शासन के उद्देश्यो एवं लाभो को समस्त मानव जाति तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूर्ण करने में शिक्षा की संभावनाएं विकसित होती है ताकि ऐसे लोगों को इसके जरिये जोडा जा सके । चूंकि देश के कई लोगों को इस सेवा के बारे में जानकारी नहीं मिलने की वजह से वह लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते है ।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन की समीक्षा के पश्चात यह कहा जा सकता है कि ई शासन किसी भी विकासशील राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है । इसके अलावा इसके माध्यम से किसी भी सरकार हेतु शासन चलाने की सुगम स्थितियों का निर्माण संभव हो सका है । किसी भी सरकारी योजना या सेवा को सीधे आम व्यक्ति तक इसके लाभांश को पहुंचाने में आज ई शासन के अवयव कार्य कर रहे हैं । वास्तव में यह एक ऐसी सर्विस है जिसमे लोगों को सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता भी नही पड़ती है, कोई भी आम व्यक्ति अपने सरकारी कामकाजों को इंटरनेट के जरिये घर बैठे या कही पर से भी आसानी से कर सकता है ।

संदर्भ सूची

1. N. S. Kalsi, Ravi Kiran and S. C. Vaidya, Effective e-Governance for Good Governance in India, International Review of Business Research Papers. 2009 Jan;5(1):212-229.
2. Dr. Pardeep Mittal, Amandeep Kaur. E-Governance - A challenge for India, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). 2013 Mar;2:3.
3. Poonam Malik, Priyanka Dhillon, Poonam Verma. Challenges and Future Prospects for E-Governance in India, International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR). 2014 Jul;3:7.
4. Kiran Yadav, Sanatan Tiwari. E-Governance in India: Opportunities and Challenges, Advance in Electronic and Electric Engineering. ISSN 2231-1297. 2014;4(6):675-680.